

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र०/NBPDCL-12/2024-

/पटना, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय :- नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के क्षेत्राधीन मधुबनी जिला अंतर्गत लदनियाँ प्रखंड के बेरहा ग्राम में एक अदद 33/11 के०भी०, 2X10 MVA क्षमता के नये विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 10.82 करोड़ (दस करोड़ बेरासी लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3.00 करोड़ (तीन करोड़) रुपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या-2085 दिनांक-27.06.2024 द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के क्षेत्राधीन मधुबनी जिला अंतर्गत लदनियाँ प्रखंड के बेरहा ग्राम में एक अदद 33/11 के०भी०, 2X10 MVA क्षमता के नये विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 10.82 करोड़ (दस करोड़ बेरासी लाख) रुपये की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.00 करोड़ रुपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4.00 करोड़ रुपये अर्थात् कुल 5.00 करोड़ रुपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध करा दिया गया है। पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त 3.00 करोड़ रुपये की मांग साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० द्वारा की गयी है, जिसे उपलब्ध कराया जाना है।

2. उक्त आलोक में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के क्षेत्राधीन मधुबनी जिला अंतर्गत लदनियाँ प्रखंड के बेरहा ग्राम में एक अदद 33/11 के०भी०, 2X10 MVA क्षमता के नये विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 10.82 करोड़ (दस करोड़ बेरासी लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3.00 करोड़ (तीन करोड़) रुपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि मांग सं०-10, मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष-0107 नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० की परियोजना, विपत्र कोड-10-4801051900107 विषय शीर्ष 54.01-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0048-नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०, व्यय शीर्ष-L8448001200048 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200048 में जमा की जाएगी।

5. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए CFMS खाता संख्या-PTSPLA018 से की जाएगी।
6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार माननीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०/NBPDCL-12/2024 के पृष्ठ संख्या-05/टि० पर दिनांक-13.06.2024 को प्राप्त है।
8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०/NBPDCL-12/2024 के पृष्ठ संख्या-32/टि० पर दिनांक-02.01.2026 को प्राप्त है।
9. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(सुधा गुप्ता)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/NBPDCL-12/2024-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/NBPDCL-12/2024-

199

/पटना, दिनांक- 13.01.2026

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग(तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि०/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।